



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 141]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 1, 2009/चैत्र 11, 1931

No. 141]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 1, 2009/CHAITRA 11, 1931

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जाँच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2009

(निर्णायक समीक्षा)

विषय : यूरोपीय संघ के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित पीवीसी पेस्ट रेजिन पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा ।

सं. 15/27/2008-डीजीएडी.—समय-समय पर यथा-संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं वसूली तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए यूरोपीय संघ (जिसे आगे संबद्ध देश/क्षेत्र कहा गया है) के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित पीवीसी पेस्ट रेजिन (जिसे आगे संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयात पर दिनांक 7 अक्टूबर, 2004 की अधिसूचना सं. 104/2004-सी.शु. के तहत मूल रूप में निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था ।

2. विचाराधीन उत्पाद

मूल मामले में विचाराधीन उत्पाद "पॉलीविनाइल क्लोराइड पेस्ट रेजिन" जिसे इमल्शन पीवीसी रेजिन के नाम से भी जाना जाता है और जिसका उल्लेख पीवीसी पेस्ट रेजिन के रूप में किया जाता है । इस निर्णायक समीक्षा जाँच के प्रयोजनार्थ विचाराधीन उत्पाद

(जिसे आगे संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) वही रहता है । पीवीसी पेस्ट रेजिन का उत्पादन विनाइल क्लोराइड मोनोमर (वीसीएम) से किया जाता है । वीसीएम का उत्पादन ईडीसी के प्रयोग द्वारा किया जाता है जिसके लिए प्रमुख उत्पाद के रूप में क्लोरीन की जरूरत होती है । संबद्ध वस्तु का उत्पादन और उसकी बिक्री सफेद/मटमैले पाउडर के रूप में की जाती है । इस उत्पाद के गुणधर्मों का उल्लेख "के" मूल्य, अंतर्निहित श्यानता, भार के आकार के अनुसार प्रतिधारण क्षमता, ताप ह्रास, आरम्भिक वीएफबी आदि के रूप में किया जाता है । समस्त ग्रेड वर्तमान जाँच की विषय वस्तु हैं और ये विचाराधीन उत्पाद के दायरे में आते हैं । पीवीसी पेस्ट रेजिन का आमतौर पर उपयोग कृत्रिम चर्म (रेक्सिन, कोटेड फैब्रिक, तिरपाल, कन्वेयर बेल्टिंग, खिलौने, ऑटोमोटीव सिलेंट, आसंजक आदि) में किया जाता है । संबद्ध वस्तु को मुक्त रूप से प्रवाह होने वाले मिश्रणों के रूप में डीओपी जैसे मिश्रणकारी तरल प्लास्टिसाइजर्स द्वारा उपभोक्ता के लिए प्रसंस्कृत किया जाता है । इन मिश्रणों अथवा पेस्टों को वस्त्र जैसे सबस्ट्रेट्स पर उचित आकार या कोट करने के लिए तैयार किया जाता है । संबद्ध वस्तु सीमाशुल्क टैरिफ शीर्ष के अध्याय 39 के सीमाशुल्क उप-शीर्ष 39042110 के अंतर्गत वर्गीकृत है ।

3. जाँच की शुरुआत

इण्डियन मेटल एण्ड फेरो एलॉयज लि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी रिट याचिका (सिविल) सं. 2006 की 16893 के मामले में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को ध्यान में रखते हुए तथा पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार प्राधिकारी एतद्वारा प्रवृत्त शुल्क को सतत रूप से लगाए जाने की जरूरत की समीक्षा करने और इस बात की जाँच करने के लिए कि क्या ऐसे शुल्क की समाप्ति से पाटन तथा क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, निर्णायक समीक्षा जाँच शुरू करते हैं ।

4. शामिल देश/क्षेत्र

इस जांच में शामिल देश/क्षेत्र यूरोपीय संघ है।

5. जांच की अवधि

वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि दिनांक 1 अप्रैल, 2008 से 31 मार्च, 2009 (12 माह) है। तथापि क्षति विश्लेषण में वर्ष 2005-06, 2006-07, 2007-08 एवं जांच अवधि शामिल हैं। पाटन एवं क्षति की संभावना का निर्धारण करने के लिए जांच अवधि के बाद के आंकड़ों की भी जांच की जा सकती है।

6. प्रक्रिया

20 अगस्त, 2004 की अधिसूचना सं. 14/14/2003-डीजीएडी के तहत जारी अंतिम जांच परिणाम तथा 7 अक्टूबर, 2004 की सी.शु. अधिसूचना सं. 104/2004 के तहत लागू अंतिम शुल्क की समीक्षा करने का निर्णय लेने के बाद प्राधिकारी एतद्वारा सीमाशुल्क (संशोधन) अधिनियम, 1995 एवं सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं वसूली तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के अनुसार प्रवृत्त शुल्क को सतत रूप से लागू रखने की जरूरत की समीक्षा करने और इस बात की जाँच करने के लिए कि क्या पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने से संबद्ध देश/क्षेत्र के मूल की या वहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों के पाटन और क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, जांच शुरू करते हैं। इस समीक्षा में 20 अगस्त, 2004 की अधिसूचना सं. 14/14/2003-डीजीएडी (मूल जाँच का अंतिम जाँच परिणाम) के सभी पहलू शामिल हैं।

7. सूचना प्रस्तुत करना

संबद्ध देशों/क्षेत्र के निर्यातकों, भारत में प्रतिनिधिक कार्यालय के जरिए संबद्ध देश/क्षेत्र की सरकारों, भारत में इस उत्पाद के संबंधित समझे जाने वाले आयातकों तथा प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग को निर्धारित प्रारूप में तथा तरीके से संबंधित सूचना प्रस्तुत करने और अपने विचारों से निर्दिष्ट प्राधिकारी को निम्नलिखित पते पर अवगत कराने हेतु अलग से पत्र भेजे जा रहे हैं:—

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
वाणिज्य विभाग
कमरा नं. 240, उद्योग भवन
नई दिल्ली-110001

अन्य कोई हितबद्ध पक्षकार भी निर्धारित प्रारूप में तथा तरीके से इस जांच से संगत अपने अनुरोध नीचे निर्धारित अवधि के भीतर प्रस्तुत कर सकता है।

8. समय सीमा

वर्तमान समीक्षा से संबंधित कोई भी सूचना तथा सुनवाई संबंधी अनुरोध लिखित में भिजवाया जाए, जो निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस (40) दिनों के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राप्त हो जाना चाहिए। यदि निर्धारित अवधि

के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती अथवा प्राप्त सूचना अधूरी है, तो निर्दिष्ट प्राधिकारी, उपर्युक्त नियमावली के अनुसरण में, रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

9. अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

सभी हितबद्ध पक्षकार उपर्युक्त नियमावली के नियम 7(1) के अनुसार प्रदत्त गोपनीय सूचना के लिए नियम 7(2) के अनुसार गोपनीय तथा अगोपनीय सारांश उपलब्ध कराएंगे। अगोपनीय रूपांतरण या गोपनीय सूचना का अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए जिससे अन्य हितबद्ध पक्षकारों को सूचना के बारे में सार्थक जानकारी उपलब्ध हो सके। यदि ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार की राय में ऐसी सूचना का सारांश व्यवहार्य नहीं है तो उसके कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराना अपेक्षित है।

उपर्युक्त पैरा में निहित किसी बात के होते हुए भी यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने अथवा उसका सामान्यीकृत रूप में या सारांश रूप में प्रकटन करने हेतु प्राधिकृत करने के लिए अनिच्छुक है तो ऐसी सूचना की अनेदखी की जा सकती है।

10. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

नियम 6(7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय पाठ वाली सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है।

11. असहयोग

यदि कोई हितबद्ध पक्षकार आवश्यक सूचना प्रस्तुत करने से मना करता है अथवा अन्यथा उचित अवधि के भीतर प्रस्तुत नहीं करता है अथवा जांच में अत्याधिक बाधा डालता है, तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्रीय सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकते हैं, जिन्हें वे उपयुक्त समझते हों।

आर. गोपालन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2009

(Sunset Review)

Subject : Sunset Review of anti-dumping duty imposed against PVC Paste Resin originating in or exported from European Union.

No. 15/27/2008-DGAD.—Whereas having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act), and the Customs

Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the AD Rules), the definitive anti-dumping duty was originally imposed *vide* Notification No. 104/2004-Customs, dated the 7th October, 2004 on import of PVC Paste Resin (hereinafter referred to as subject goods) originating in or exported from European Union (hereinafter referred to as the subject country/territory).

2. Product under consideration :

The product under consideration in the original case was "Poly Vinyl Chloride Paste Resin" also called Emulsion PVC Resin and referred to as PVC Paste Resin. The product under consideration remains the same for the purposes of this Sunset Review investigation (hereinafter also referred to as the subject goods). The PVC Paste Resin is produced from Vinyl Chloride Monomer (VCM). VCM is produced using EDC, which in turn requires chlorine as one of the major products. The subject goods is produced and sold in the form of white/off-white powder. The properties of the product are described in terms of K value, inherent viscosity, particle size retention, heat loss, initial BFB etc. All grades are subject-matter of present investigation and are within the scope of product under consideration. Common applications of PVC Paste Resin are artificial leather (Rexene, coated fabrics, tarpaulins, conveyer beltings, toys, automotive sealant, adhesives etc. The subject good is processed at consumer end, by mixing liquid plasticizers like DOP to form free flowing mixtures. These mixtures or pastes are formed to suitable shapes or coated on sub-straits like textiles. The subject good is classified under Chapter 39 of the Customs tariff head within the Customs sub-heading 39042110.

3. Initiation :

In view of the order of the Hon'ble Delhi High Court in the matter of Indian Metal and Ferro Alloys Ltd. V/s. Designated Authority, Writ Petition (Civil) No. 16893 of 2006 and in accordance with Section 9A(5) of the Act, read with Rule 23 of Anti-dumping Rules, the Authority hereby initiates a sunset review investigation to review the need for continued imposition of duties in force and to examine whether the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

4. Country/territory involved :

The country/territory involved in this investigation is European Union.

5. Period of Investigation :

The Period of Investigation (POI) for the purpose of the present review is 1st April, 2008 to 31st March, 2009 (12 months). However, injury analysis shall cover the years 2005-06, 2006-07, 2007-08 and POI. The data beyond POI may also be examined to determine likelihood of dumping and injury.

6. Procedure :

Having decided to review the final findings issued *vide* Notification No. 14/14/2003-DGAD, dated 20th August, 2004 and final duty imposed *vide* Customs Notification No. 104/2004, dated 7th October, 2004, the Authority hereby initiates investigations to review the need for continued imposition of duties in force and to examine whether cessation of Anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of Dumping and injury on imports of subject goods originating in or exported from subject country/territory in accordance with the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995. The review covers all aspects of Notification No. 14/14/2003-DGAD, dated 20th August, 2004 (final findings of the original investigation).

7. Submission of Information :

The exporters in subject country/territory, the governments of subject country/territory through its representative office in India, the importers and users in India known to be concerned with the product and the domestic industry, are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

Government of India

Ministry of Commerce and Industry

Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties

Department of Commerce

Room No. 240, Udyog Bhavan, New Delhi-110001

Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

8. Time Limit :

Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Designated Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules *supra*.

9. Submission of information on non-confidential basis :

All interested parties shall provide a confidential and non-confidential summary in terms of Rule 7 (2), for the confidential information provided as per Rule 7 (1) of the Rules *supra*. The non-confidential version or

non-confidential summary of the confidential information should be in sufficient detail to provide a meaningful understanding of the information to the other interested parties. If in the opinion of the party providing such information, such information is not susceptible to summary; a statement of reasons thereof is required to be provided.

Notwithstanding anything contained in para above, if the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalised or summary form, it may disregard such information.

10. Inspection of public file :

In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

11. Non-cooperation

In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Governments as deemed fit.

R. GOPALAN, Designated Authority